

पहले मुख्य समाचार।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा सुजलम भारत की स्थापना को भी मिली मंत्रिमंडल की स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पारित हुई मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-दो हजार छब्बीस। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा- योजना के माध्यम से प्रदेश के हर गांव तक पहुंचेगी बस सेवा।
- मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों और आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा। अधिकारियों को सतर्कता के साथ दायित्व निभाने का दिया निर्देश।
- केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं को किया आश्वस्त। कहा-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए देश में ईंधन की कोई कमी नहीं।

\*\*\*\*\*

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर दो हजार अट्ठाइस तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इस जल-जीवन मिशन का टू प्वाइंट ओ वर्जन एपूव हुआ। वन प्वाइंट ओ वर्जन इतना महत्वकांक्षी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑपरेशन इन मेटेनेंस, वॉटर सोर्स, सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमेटी बनी है, विलेज की कमेटी, ग्रामसभा की कमेटी, पंचायत की कमेटी इन सबको इवॉल्व करना फिर जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहां पर नए सोर्सिस निकलना एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया। शुरु में टेकऑफ करना कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना।

मंत्रिमंडल ने एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा, "सुजलम भारत", स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव आईडी आवंटित की जाएगी। इससे स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने नोएडा के जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना के लिए तीन हजार 630 करोड़ 77 लाख रुपये मंजूर किए हैं। करीब साढ़े 31 किलोमीटर लंबा यह गलियारा दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधे और तीव्र गति का संपर्क जरिया बनेगा।

जैवर एयर पोर्ट की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से भी, हरियाणा से भी और दिल्ली से भी। इस कनेक्टिविटी को आप स्टडी करे अगर तो एक तो यमुना एक्सप्रेस-वे के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो गई, दूसरा जो मुम्बई-दिल्ली एक्सप्रेस-वे है इसके साथ कनेक्टिविटी और दिल्ली के एरिया के साथ इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी।

\*\*\*\*\*

इस बीच जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर भारत सरकार की ओर से जारी एयरोड्रम लाइसेंस प्रस्तुत किया। इस लाइसेंस के मिलने के बाद अब एयरपोर्ट के उद्घाटन और वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक रिपोर्ट-

एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नेलमैन समेत वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को मुलाकात के दौरान परियोजना की प्रगति और आगामी चरणों की जानकारी भी दी। गौतमबुद्ध नगर के जेवर में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट का विकास चार चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल भवन बनाया गया है, जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। दूसरे चरण में क्षमता बढ़ाकर 3 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी। तीसरे और चौथे चरण में विस्तार के बाद कुल क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार कक्ष से समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

\*\*\*\*\*

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को स्वीकृति दे दी। इस योजना के माध्यम से अब उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बस पहुंचेगी। योजना के तहत निजी बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी। इन बसों को परमिट और टैक्स से मुक्त रखा गया है।

हम लोग यह नई पॉलिसी लाए हैं कि उत्तर प्रदेश के उनसठ हजार एक सौ तिरसठ गांवों में बस जाए सभी गांवों में। इसकी विशेषता यह होगी कि एक तो पहले यह टैक्स फ्री होगा। प्राइवेट लोगों को हम इसको चलाने की अनुमति देंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में एस. पी., सी.डी.ओ. और हमारे ए.आर.टी.ओ. और हमारे आर. एम. जो होते हैं हमारे लोकल लेवल पर, ये इसके मेम्बर होंगे।

राज्य सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर अब ओला, उबर जैसी टैक्सी का पंजीकरण कराना अनिवार्य करने के साथ ही जनहित में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक रिपोर्ट—

**अब ओला और ऊबर जैसी कम्पनियों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में पंजीकरण कराना होगा। परिवहन निगम एक ऐप भी बनायेगा, जिसमें ओला और ऊबर की गाड़ियों और उसके चालक की पूरी जानकारी होगी। कैबिनेट द्वारा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी, जिसके अनुसार अब प्रापर्टी बेचने वालों की पहचान को खतौनी में देखा जायेगा। बिना मालिकियत की जांच किये बगैर अब स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। राजस्व मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।**

\*\*\*\*\*

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों और आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट—

**समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया कि चौदह और पन्द्रह मार्च को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केन्द्रों के बाहर पीआरवी-112 वाहनों की तैनाती की जाए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि परीक्षा शुचिता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के 1090 परीक्षा केन्द्रों पर चार पालियों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 15 लाख 75 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। श्री योगी ने कहा कि 13 मार्च को अलविदा की नमाज, 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ और 20 या 21 मार्च को ईद-उल-फ़ितर मनाए जाने की सम्भावना है। ऐसे में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। समाचार कक्ष से मैं अरुण।**

\*\*\*\*\*

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 177 छात्रों को डिग्रियां प्रदान कीं। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त डॉ नवीन बी. महेश्वरप्पा उपस्थित रहे।

\*\*\*\*\*

केन्द्र सरकार ने आश्वासन दिया कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई वजह नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से लगातार जारी है। एक रिपोर्ट—

**घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है, साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल तय किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि अन्य गैर घरेलू क्षेत्रों जैसे रैस्तरां, होटल और अन्य उद्योगों के लिए एलपीजी आपूर्ति से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति भी बनाई गई है। आरजू के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।**

\*\*\*\*\*

प्रसार भारती का ऑडियो-विजुअल प्रसारण और प्रसार मंच-पीबी-शब्द अगले वर्ष मार्च तक, लोगो रहित समाचार सामग्री प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध कराता रहेगा। मंत्रालय ने बताया है कि पीबी-शब्द के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सामग्री लोगो रहित है और इसका उपयोग करते समय पीबी-शब्द का उल्लेख करना जरूरी नहीं है।

\*\*\*\*\*